छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

रायपुर, दिनांक 20.06.2010

-अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन प्रारंभ
- अध्यक्ष विधान सभा श्री धरम लाल कौशिक ने समिति प्रणाली को प्रभावी बनाने पर विचार व्यक्त किये

अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज श्रीनगर में लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार को गार्ड ऑफ आनर के साथ प्रारंभ हुआ। सम्मेलन की कार्यवाही का प्रारंभ जम्मू-कश्मीर विधान सभा के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर लोन के स्वागत भाषण एवं लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के उद्घाटन सम्बोधन के साथ हुआ।

श्रीमती मीरा कुमार ने अपने उद्घाटन भाषण में लोकसभा में संसदीय प्रश्नों के संबंध में लिए गये कुछ उपायों की जानकारी देते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसे प्रभावी बनाने के लिए गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, इसी प्रकार उन्होंने विधानसभा की समितियों के महत्व विषय समितियों एवं अन्य समितियों के कार्यकरण में किस प्रकार से परिमार्जन किया जाये इस पर पीठासीन अधिकारियों से अपने सम्मेलन के दौरान विचार व्यक्त करने के लिए आग्रह किया।

आज सम्मेलन में समिति प्रणाली का महत्व एवं इसे प्रभावी बनाने के विषय पर लगभग 20 पीठासीन अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किये। अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा श्री धरम लाल कौशिक ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के समस्त विधान मण्डलों में घटती हुई बैठकों की संख्या के कारण समितियों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि समितियां जिन्हें सभा के समान ही अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है वर्षभर कार्यपालिका को विधानमण्डल के प्रति उत्तरदायी बना सकती है।

उन्होंने समितियों के कार्यकरण में कार्यपालिका का अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं होने पर भी चिंता व्यक्त की। इस संदर्भ में राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा समितियों की बैठकों का सभापतित्व करने एवं समितियों को वांछित सहयोग नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग की कार्यवाही आरंभ करने जैसे निर्णय पर भी यह व्यक्त किया कि क्या अध्यक्ष से ऐसा किया जाना अपेक्षित है और क्या यह उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है? उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि समितियां अपना कार्य प्रभावी रूप से करे इस हेतु कार्यपालिका का पूर्ण सहयोग प्राप्त होना आवश्यक है और कार्यपालिका का यह दायित्व है कि वांछित जानकारियां शासन के विभाग त्वरितता के साथ उपलब्ध कराने एवं समिति की अनुशंसाओं पर शासन द्वारा कार्यवाही किया जाना बंधनकारी हो। उन्होंने सिफारिशों के स्थान पर निर्देश शब्द का भी उपयोग करने पर जोर दिया।

उल्लेखनीय है कि कल दिनांक 21 जून 2010 को अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा रखे गए विषय "प्रश्नकाल को बाधित करने की प्रवृत्ति तथा इसे रोकने एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता" पर श्री कौशिक चर्चा को आरंभ करेंगे।